

पी. एन. वीती नारायणी

बनाम

पथुम्मा बीवी और अन्य

सितंबर 13,1990

[न्यायाधिपति ए. एम. अहमदी और न्यायाधिपति मदन मोहन पंजी]

परिसीमा अधिनियम: धारा 18, 19 और 20--की स्वीकृतिऋण-जब सीमा बचाता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ-ऋण चुकाने की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है उत्तराधिकारियों की संपत्ति में उनके संबंधित शेयरों के अनुपात में मृतक।

मृतक वेल्लाप्पा रावथर ने 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के दो वचन पत्रों के माध्यम से कर्ज लिया था। वचन पत्रों के आधार पर दायर मुकदमे में, ट्रायल कोर्ट ने वेल्लाप्पा रावथर की संपत्ति के खिलाफ डिक्री दे दी। प्रतिवादी 2 से 10 अपील पर उच्च न्यायालय ने डिक्री को संशोधित कर इसे डिक्री की गई राशि के एक चौथाई तक कम कर दिया और प्रतिवादी/प्रतिवादी नंबर 2 पर दायित्व केंद्रित कर दिया और सीमा की सीमा पर शेष दायित्व से दूसरों को मुक्त कर दिया। इस तरह का दृष्टिकोण इसलिए लिया गया क्योंकि तथ्यों से यह स्थापित हो गया कि वेल्लाप्पा के ऋणों का भुगतान करने का दायित्व था। रावथर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से संपत्ति में उनके हिस्से की सीमा के

अनुपात में उन्हें हस्तांतरित किया गया था, और चूंकि ऋण कालातीत हो गया था, उसी प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 की पावती के साथ-साथ ऋण का आंशिक भुगतान भी किया गया था। उसने संपत्ति के हिस्से से संबंधित एक चौथाई की सीमा तक दायित्व को पूरा करने के लिए उसे अकेले ही उत्तरदायी बना दिया, जो कि एक मुस्लिम उत्तराधिकारी के रूप में उसे मृतक से प्राप्त हुआ था।

इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता की ओर से यह दावा किया गया था कि सीमा अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत पावती और आंशिक भुगतान ने सभी के खिलाफ सीमा को बचा लिया और इस प्रकार संयुक्त रूप से पड़ी संपत्ति के कब्जे में होने के कारण प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 2 से पूरा ऋण वसूल किया जा सकता है।

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

(1) मृतक का ऋण मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति में उनके शेयरों के अनुपात में उत्तराधिकारियों के बीच शेयरों में विभाजित हो जाता है। ऋण की अखंडता की पवित्रता का सिद्धांत स्पष्ट रूप से एक मृत मुस्लिम द्वारा ऋण छोड़ने और कुछ संपत्ति दोनों उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित होने के मामले में विदेशी है। [247 जी]

मोहम्मद. अब्दुल कादिर बनाम अजामतुल्लाह खान और 8 अन्य, [1974] 1 आंध्र साप्ताहिक रिपोर्टर 98; वसंतम सांबशिव राव बनाम श्री कृष्ण सीमेंट एंड कंक्रीट वर्क्स, तेनाली 1977 आंध्र लॉ टाइम्स 528 पर रिपोर्ट करता है; एन. के. मोहम्मद सुलेमान बनाम एन. सी. मोहम्मद इस्माइल और अन्य, [1966] 1 एस. सी. आर. 935- 940 पर, संदर्भित।

(2) यह तय मानना सही होगा कि मुस्लिम उत्तराधिकारी मृतक की संपत्ति और ऋण में एक साथ अपने विशिष्ट शेयरों के स्वतंत्र मालिक हैं, व्यक्तिगत कानून के तहत उनकी देनदारी उनके शेयरों की सीमा के अनुपात में तय की गई है। [248 एच]

जाफरी बेगम बनाम अमीर मुहम्मद खान, [1885] खंड 7 आईएलआर इलाहाबाद श्रृंखला, संदर्भित।

(3) किसी मुसलमान के उत्तराधिकारी स्वयं स्वतंत्र देनदार होते हैं, कानून के संचालन से ऋण का बंटवारा हो जाता है। परस्पर, सह-देनदार या संयुक्त देनदार के रूप में उनका कोई न्यायिक संबंध नहीं है ताकि वे ठेकेदारों, साझेदारों, निष्पादकों या गिरवीदारों की छाया में या उनके जैसे किसी वर्ग में आ सकें। वे विशिष्ट शेयरों में किरायेदारों के रूप में संपत्ति में सफल होते हैं। [250 डी]

(4) यहां तक कि प्रिंसिपल या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित लिखित पावती भी प्रिंसिपल को बाध्य करेगी, न कि किसी अन्य को जो प्रिंसिपल के साथ न्यायिक संबंध में है, सीमा अधिनियम की धारा 20 (2) के

अनुसार मुस्लिम उत्तराधिकारियों के पास ऐसा कोई मामला नहीं है। संबंध।  
[250 ई]

5) यदि ऋण एक और अविभाज्य है, तो एक द्वारा भुगतान सभी देनदारों के खिलाफ सीमा को बाधित करेगा जब तक कि वे धारा 20 (2) में निर्धारित अपवाद के भीतर नहीं आते। और यदि ऋण विभाजन के लिए अतिसंवेदनशील है और यद्यपि प्रतीत होता है कि इसमें वास्तव में कई अलग-अलग ऋण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को देनदारों में से एक द्वारा अलग से भुगतान किया जाना चाहिए और बाकी द्वारा नहीं, धारा 20 ऋण के उसके हिस्से को जीवित रखती है जिसे चुकाना होता है। वह व्यक्ति जिसने ब्याज का भुगतान किया है। यह अन्य देनदारों के अलग-अलग शेयरों को प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक कि एजेंसी के मूलधन पर, व्यक्त या निहित, भुगतान को उनकी ओर से भी भुगतान नहीं कहा जा सकता है। [ 250 एच; 251 ए]

अभेश्वरी दास्या और एक अन्य बनाम बाबुराली शेख और अन्य, ए.  
आई. आर. 1937 कैल 191, संदर्भित किया गया।

(6) कथित रूप से प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 के कब्जे में सह-वारिसों की संपत्ति को सीधे उसके हाथ में नहीं छुआ जा सकता है, जब तक कि मुकदमे के पक्षकार सह-वारिसों को ऋण के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है; ऋण वसूली योग्य है, [251 एफ)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 229/1976

1974 के ए.एस.संख्या 76 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 6.9.1974 से।

एस. पद्मनाभन, के. प्रशांति और एन. सुधा-करण अपीलार्थी के लिए ।  
सुश्री श्यामला पप्पु, जी. विश्वनाथन अय्यर, वी. बी. सहारिया और श्रीमती सरिया चंद्र प्रतिवादी के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति पंची

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील केरल उच्च न्यायालय द्वारा 1974 के एएस संख्या 76 में पारित दिनांक 6.9.1974 के फैसले और डिक्री के खिलाफ है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के डिक्री को घटाकर एक चौथाई कर दिया और शेष तीन-चौथाई को अस्वीकार कर दिया। आधार यह है कि यह सीमा द्वारा वर्जित था। उसमें वादी-अपीलकर्ता हमारे सामने जोखिम उठाता है। विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल करने के लिए। चूंकि प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2, संद्र मोहम्मद रॉथर को स्थापित दायित्व को पूरा करना है, इसलिए उनकी ओर से, हालांकि काफी देर से, मुकदमे के आंशिक डिक्री पर क्रॉस-ऑब्जेक्ट करने की अनुमति मांगने का प्रयास किया गया है।

इसे जन्म देने वाले तथ्य वास्तव में विभिन्न और विविध थे, जो पहली बार अप्रैल 1967 में विचारण न्यायालय द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाए गए चार मुकदमों में शामिल थे। पीड़ित पक्षों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चार अपीलें दायर की गईं। जिनमें से तीन का निपटारा 11-9-1972 को एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया। 1965 की ओ.एस.संख्या 141 से उत्पन्न चौथी अपील में वादी-अपीलकर्ता को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी ताकि कुछ दस्तावेजों में निहित स्वीकृतियों की सहायता से दो वचन पत्रों के आधार पर उसके पैसे के मुकदमे को आधार बनाया जा सके। रिमांड के आदेश के अनुसरण में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के खिलाफ 56,769.80 रुपये की राशि, उस पर 11-11-1964 से 31-7-1955 तक और उसके बाद 6-1/4 प्रतिशत ब्याज के साथ डिक्री दी। प्रतिवादी 2 से 10 के हाथों में वेल्लप्पा रॉथर की संपत्ति के विरुद्ध आनुपातिक लागत के साथ, भुगतान तक प्रति वर्ष प्रतिशत; और पहले प्रतिवादी-प्रतिवादी के खिलाफ एक निश्चित राशि के लिए एक और व्यक्तिगत डिक्री जो वर्तमान में विवाद में नहीं है। उच्च न्यायालय ने 1965 के मूल वाद संख्या 141 (केवल एक ही जीवित है) में प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 2 और 4-10 द्वारा की गई अपील पर डिक्री को संशोधित किया और इसे निर्धारित राशि के एक चौथाई तक कम कर दिया और अन्य को दोषमुक्त करते हुए प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 2 पर दायित्व केंद्रित कर दिया। सीमा की सीमा पर शेष देनदारी के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण स्थापित तथ्यों पर लिया गया था कि 23-11-1960 और 5-1-

1961 के दो वचन पत्रों के माध्यम से 25,000 रुपये के मृतक वेल्लाप्पा रावथर के ऋणों का निर्वहन करने की देनदारी और 26-6-1962 को वेल्लाप्पा राँथर की मृत्यु के बाद क्रमशः 50,000 रुपये, उनके उत्तराधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें हस्तांतरित संपत्ति में उनके हिस्से की सीमा के अनुपात में थे और चूंकि ऋण कालातीत हो गया था, उसी की स्वीकृति प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 के साथ-साथ उसके द्वारा ऋण के आंशिक भुगतान ने उसे संपत्ति के हिस्से से संबंधित एक चौथाई की सीमा तक दायित्व को पूरा करने के लिए अकेले उत्तरदायी बना दिया, जो एक मुस्लिम उत्तराधिकारी के रूप में उसे मृतक से प्राप्त हुआ था। इस अपील में वादी-अपीलकर्ता की ओर से यह दावा किया गया है कि पावती और आंशिक भुगतान को सभी के खिलाफ बचाई गई सीमा के लिए संदर्भित किया गया है और इस प्रकार पूरे ऋण को प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 से वसूल किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास संयुक्त रूप से पड़ी संपत्ति का कब्जा है। , और इस प्रकार विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द करने में उच्च न्यायालय की गलती थी।

अपीलकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि दो वचन पत्र प्रदर्शनी बी 14 और बी 15 द्वारा बनाए गए 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के दो ऋणों की अखंडता को इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता है कि उन ऋणों को चुकाने की देनदारी को हस्तांतरित किया जाए। मृतक देनदार के वारिसों को मुस्लिम कानून में ज्ञात उनके शेयरों के अनुपात में

यह अपीलकर्ता की ओर से यह भी आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किए गए दायित्व की स्वीकृति सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत न केवल उसके खिलाफ बल्कि उसके खिलाफ भी सीमा को बचाएगी। अन्य उत्तराधिकारियों के विरुद्ध भी, क्योंकि माना जाता है कि उसने उनकी ओर से प्रतिनिधि एजेंट या भागीदार के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किए गए आंशिक भुगतान से मृतक महोमेदान देनदार के अन्य सह-वारिसों के खिलाफ सीमा अधिनियम की धारा 19 के तहत सीमा से बचा जा सकेगा। मोहम्मद अब्दुल कादिर बनाम अज़मतुल्ला खान और 8 अन्य (1974] 1 आंध्र वीकली रिपोर्टर 98) मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए विचार को यह तर्क देने के लिए सेवा में लगाया गया है कि हालांकि मुस्लिम कानून के तहत प्रत्येक उत्तराधिकारी ऋण के लिए उत्तरदायी है। मृतक के ऋणों के केवल एक हिस्से की सीमा तक, संपत्ति के उसके हिस्से के अनुपात में, लेकिन जहां तक संपादक का सवाल है, ऋण की पहचान और अखंडता मूल वचनदाता की मृत्यु से अप्रभावित रहती है और कई ऋण सामने नहीं आते हैं एक ऋण के स्थान पर।

हालाँकि, पूरी निष्पक्षता से अगली सांस में हमें पता चला कि उसी उच्च न्यायालय के एक और एकल न्यायाधीश वसंतम संबाशिव राव बनाम श्री कृष्णा सीमेंट और कंक्रीट वर्क्स, तेनाली [1977] 528 में आंध्र लॉ



टाइम्स रिपोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल कादिर के मामले (सुप्रा) में उस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच मामले के आधार पर इस विचार पर संदेह किया कि सीमा की धारा 19 अधिनियम में ऋण की पहचान या अखंडता पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि देनदारों में से एक या दूसरे द्वारा उनसे देय ऋण के लिए आंशिक भुगतान करने के लिए उचित प्राधिकरण पर जोर दिया गया, और इसके अलावा कई लोगों से देय ऋण की पहचान और अखंडता की अवधारणा पर जोर दिया गया। धारा 19 और 20 के तहत उत्तराधिकारी विदेशी थे।

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एन.के. मोहम्मद सुलेमान बनाम एन.सी. मोहम्मद इस्माइल और अन्य, [1966] 1 एससीआर 935 पृष्ठ 940 पर इस न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस विषय पर मुस्लिम कानून के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से दोहराना और दोहराना उचित होगा। कुछ सुस्थापित और सर्वमान्य सिद्धांत निकाले गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

"बिना वसीयत के मरने वाले मुस्लिम की संपत्ति उसकी मृत्यु के समय इस्लामी कानून के तहत उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है, यानी व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्धारित हिस्से के अनुपात में संपत्ति तुरंत प्रत्येक उत्तराधिकारी में निहित हो जाती है और प्रत्येक उत्तराधिकारी का हित अलग और अलग होता है। वारिस

व्यक्तिगत कानून के तहत मृतक के ऋण को केवल संपत्ति में उसके हिस्से के अनुपातिक ऋण के हिस्से की सीमा तक चुकाने के लिए उत्तरदायी है।"

उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि मृतक का ऋण मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति में उनके शेयरों के अनुपात में शेयरों में विभाजित हो जाता है। ऋण की अखंडता की पवित्रता का सिद्धांत स्पष्ट रूप से एक मृत मुस्लिम द्वारा ऋण छोड़ने और कुछ संपत्ति दोनों को उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित करने के मामले में विदेशी है।

ए.ए.ए. फ़िजी ने अपने मुस्लिम कानून की रूपरेखा (चौथा संस्करण) में पृष्ठ 385 पर मुल्ला को यह कहते हुए उद्धृत किया है:

"तार्किक रूप से आगे बढ़ते हुए, ध्यान में रखा जाने वाला पहला सिद्धांत यह है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी मृतक के ऋणों के लिए उसे विरासत में मिलने वाले हिस्से के अनुपात में उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए, एक मुस्लिम तीन उत्तराधिकारियों को छोड़कर मर जाता है, जो संपत्ति को आपस में बांट लेते हैं। उनके अधिकारों के अनुसार। मृतक का एक लेनदार दो उत्तराधिकारियों पर मुकदमा करता है तीसरा नहीं; मुकदमा दायर करने वाले दोनों वारिसों में से प्रत्येक को विरासत के अपने हिस्से के अनुपात में ऋण का एक हिस्सा चुकाना होगा, और उन्हें पूरे

ऋण का भुगतान संयुक्त रूप से या अलग-अलग नहीं करना होगा .. ।"

मुल्ला द्वारा लिखित मुस्लिम कानून के सिद्धांतों, 17 वें संस्करण में, धारा 43 और 46 प्रदान करते हैं:

"43. ऋणों के लिए उत्तराधिकारियों की देनदारी की सीमा-प्रत्येक उत्तराधिकारी मृतक के ऋणों के लिए संपत्ति में उसके हिस्से के अनुपातिक ऋणों के एक हिस्से की सीमा तक ही उत्तरदायी है।

46. उत्तराधिकारियों के विरुद्ध लेनदार द्वारा मुकदमा-यदि कोई निष्पादक या प्रशासक नहीं है, तो लेनदार मृतक के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, और जहां मृतक की संपत्ति उत्तराधिकारियों के बीच वितरित नहीं की गई है, वह उसके विरुद्ध डिक्री निष्पादित करने का हकदार है। उत्तराधिकारियों की परस्पर देयता की सीमा की परवाह किए बिना समग्र रूप से संपत्ति।"

यह सवाल कि क्या बिना वसीयत किए गए किसी मुसलमान का स्वामित्व उसके उत्तराधिकारियों को तुरंत मिल जाता है, और इस तरह का हस्तांतरण आकस्मिक नहीं है और तब तक निलंबित है, जब तक कि ऐसे ऋणों का भुगतान लगभग एक सदी पहले लाफरी बेगम बनाम अमीरमुहम्मद खान [1885 ]खंड 7 आईएलआर-इलाहाबाद सीरीज

नकारात्मक में। बल्कि यह आधिकारिक रूप से तय किया गया था (रिपोर्ट का पृष्ठ 843 देखें) कि मुसलमान उत्तराधिकारी अपने विशिष्ट शेयरों के स्वतंत्र मालिक हैं और यदि वे अपने शेयरों को मृतक के ऋण के प्रभार के अधीन लेते हैं, तो उनका दायित्व उनके शेयरों की सीमा के अनुपात में होता है।

जाफरी बेगम के मामले (सुप्रा) में ये टिप्पणियाँ मुस्लिम निर्वसीयत के उत्तराधिकारियों के हाथों में ऋण की विभाज्यता के सिद्धांत की प्रमुख जड़ें हैं। इसलिए इसे मुस्लिम के तौर पर सुलझाना उचित होगा।

उत्तराधिकारी मृतक की संपत्ति और ऋण में एक साथ अपने विशिष्ट शेयरों के स्वतंत्र मालिक होते हैं, व्यक्तिगत कानून के तहत उनकी देनदारी उनके शेयरों की सीमा के अनुपात में तय होती है। कानून की इस स्थिति में इस विषय से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य निर्णयों का उल्लेख करना अनावश्यक होगा। तो हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि जितने वारिस, जितने इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उतनी संख्या में कर्ज भी है।

अब एकजिबिट्स बी7 और बीएस 1 एकजिबिट बी7 को विज्ञापन देने का समय आ गया है, प्रतिवादी-प्रतिवादी-नंबर 2 ने वादी-अपीलकर्ता को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि वह दो महीने के भीतर वादी और अन्य सभी को देय सभी राशियों का भुगतान कर देगा। विचारण न्यायालय ने इसे ऋण की स्वीकृति माना। उच्च न्यायालय उस निष्कर्ष से

सहमत था कि दस्तावेज़ में लिखित रूप में एक पावती शामिल थी, व्यावहारिक रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष इस निष्कर्ष के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया था। फिर हमारे पास एक्ज़िबिट बीएस 1 है जिसे एक सहमति-विलेख के रूप में स्टाइल किया गया है, जिसे प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा निष्पादित किया गया है, जो पहले प्रतिवादी-प्रतिवादी को 13,000 रुपये की राशि के लिए दो मोटर कारों का निपटान करने और अपने मृत पिता की देनदारियों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करता है। उपरोक्त दो वचन पत्र प्रदर्शनी बी 14 और बी 15 से उत्पन्न हुआ। विचारण न्यायालय ने पाया कि एक्ज़िबिट बीएस 1 ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 19 के अर्थ के तहत प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में एक एजेंसी बनाई। उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमत हुआ और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विलेख प्रदर्शनी बी 51 में एक पावती और संबंधित वचन पत्र प्रदर्शनी बी 14 और बी 15 पर किए गए दो समर्थन शामिल थे, जो विधिवत ऋण के लिए रकम के भुगतान से जुड़े थे। प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 के अधिकृत एजेंट को सीमा अधिनियम की धारा 19 के तहत सीमा के विस्तार को आकर्षित करने वाले भुगतान के रूप में माना जा सकता है। यह दर्ज करने के बाद कि उच्च न्यायालय ने खुद को इस सवाल पर निर्देशित किया कि क्या इस प्रकार किए गए भुगतान से अन्य उत्तराधिकारियों के खिलाफ भी सीमा बढ़ जाएगी और इसे नकारात्मक माना जाएगा। निष्कर्ष यह है कि पावती प्रदर्शनी बी 7 और प्रदर्शनी बी 51 के अधिकार पर प्रदर्शनी बी 14 और बी 15 पर समर्थन को केवल प्रतिवादी

प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ सीमा की अवधि बढ़ाने के लिए माना गया था, हालांकि हमें इन दस्तावेजों की पुनर्व्याख्या पर एक विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए संबोधित किया गया है। लेकिन, इस संबंध में विद्वान वकील को सुनने के बाद हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं और तथ्यों के क्षेत्र में कदम रखने से इनकार करते हुए मामले को बिना किसी बाधा के छोड़ देते हैं।

परिसीमा अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) (1908 के निरस्त अधिनियम IX की धारा 19 के अनुरूप) इस प्रकार प्रदान करती है:

"जहां, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में की गई है जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है, या किसी व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपना शीर्षक या दायित्व प्राप्त करता है, एक नई पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे।"

धारा 20 की उप-धारा (2) (1908 के निरस्त अधिनियम IX की धारा 21 के अनुरूप) कहती है कि उक्त धाराओं (धारा 18 और 19 होने के नाते) में कुछ भी संयुक्त ठेकेदारों, भागीदारों, निष्पादकों या गिरवीदारों में से किसी एक को कारण के आधार पर प्रभार्य नहीं बनाता है। केवल उनके

द्वारा हस्ताक्षरित लिखित पावती, या उनमें से किसी अन्य या अन्य के एजेंट द्वारा किए गए भुगतान की।

बिना वसीयत किए मरने वाले मुस्लिम के वारिस, जिन पर हस्तांतरित संपत्ति में उनके संबंधित शेयरों के अनुपात में ऋण का भुगतान करने का दायित्व आता है, उन्हें शायद ही संयुक्त ठेकेदारों, साझेदारों, निष्पादकों या बंधक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे स्वयं स्वतंत्र देनदार हैं; कानून के क्रियान्वयन से ऋण का बंटवारा हो गया है। परस्पर सह-ऋणी या संयुक्त देनदार के रूप में उनका कोई न्यायिक संबंध नहीं है ताकि वे ठेकेदारों, भागीदारों, निष्पादकों या गिरवीदारों की छाया में या उनके समान वर्ग में आ सकें। वे विशिष्ट शेयरों में आम किरायेदार के रूप में संपत्ति में सफल होते हैं। यहां तक कि प्रिंसिपल या उसके एजेंट के माध्यम से हस्ताक्षरित लिखित पावती भी धारा 20(2) के अनुसार प्रिंसिपल को बाध्य करेगी, न कि प्रिंसिपल के साथ न्यायिक संबंध में खड़े किसी अन्य व्यक्ति को। मुस्लिम उत्तराधिकारियों का आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम यह मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने ऋणों की स्वीकृति को केवल प्रतिवादी नंबर 2 तक ही सीमित रखा और अन्य सह-उत्तराधिकारियों को उनकी स्वतंत्र स्थिति के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की।

परिसीमा अधिनियम की धारा 19, (1908 के निरस्त अधिनियम IX की धारा 20 के अनुरूप), जहां तक हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, यह

प्रावधान करती है कि जहां ऋण या विरासत पर ब्याज का भुगतान समाप्ति से पहले किया जाता है ऋण या विरासत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या इस संबंध में विधिवत अधिकृत उसके एजेंट द्वारा निर्धारित अवधि के बाद, सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब भुगतान किया गया था।

संदर्भ में, यदि ऋण एक है और अविभाज्य है, तो एक द्वारा भुगतान सभी देनदारों के खिलाफ सीमा को बाधित करेगा जब तक कि वे धारा 20(2) में निर्धारित अपवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसे पहले ही नोट कर लिया गया है। और यदि ऋण विभाजन के लिए अतिसंवेदनशील है और यद्यपि प्रतीत होता है कि इसमें वास्तव में कई अलग-अलग ऋण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को देनदारों में से एक द्वारा अलग से भुगतान किया जाता है और बाकी द्वारा नहीं, धारा 20 ऋण के उसके हिस्से को जीवित रखती है जो होना चाहिए उस व्यक्ति द्वारा छुट्टी दे दी गई जिसने ब्याज का भुगतान कर दिया है। यह अन्य देनदारों के अलग-अलग शेयरों को प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक कि एजेंसी के मूलधन पर, व्यक्ति या निहित, भुगतान को उनकी ओर से भी भुगतान नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में देखें अभेश्वरी दास्य और अन्य बनाम बाबूराली शेख और अन्य, एआईआर 1937 कैल 191 प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा एक स्वतंत्र देनदार के रूप में ऋण के कारण किया गया भुगतान, न कि एक एजेंट के रूप में, व्यक्ति या निहित, अन्य की ओर से स्थापित तथ्यों के



अनुसार सह-उत्तराधिकारियों को शायद ही सभी की ओर से भुगतान कहा जा सकता है ताकि सभी के विरुद्ध परिसीमा की अवधि बढ़ाई जा सके। इस प्रकार हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने ऋण के एक हिस्से के भुगतान पर सीमा के विस्तार को केवल प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ सीमित कर दिया था, जो कि उसे सौंपी गई संपत्ति के उसके हिस्से के अनुपात में था, जो कि एक चौथाई था। हमारा यह भी मानना है कि उच्च न्यायालय ने अन्य सह-उत्तराधिकारियों के खिलाफ मुकदमे को उनके ऋण के शेयरों से संबंधित सीमा से प्रतिबंधित करने का फैसला सही किया था।

अंत में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया कि वह भी यद्यपि मृतक के ऋणों को विभाज्य माना जाता है और उनके शेयरों के अनुपात में उत्तराधिकारियों को अलग-अलग वितरित किया जाता है, फिर भी वादी प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 से पूरे ऋण की वसूली के लिए आगे बढ़ सकता है क्योंकि वह अभी भी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। और अन्य सह-उत्तराधिकारियों के साथ विभाजन के माध्यम से इससे अलग नहीं हुआ था। जाफरी बेगम के मामले (सुप्रा) के पृष्ठ 841-42 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के स्पष्ट बयान को देखते हुए यह तर्क एक पल के लिए भी टिक नहीं सकता है। इस तरह के प्रश्न को प्रक्रियात्मक कानून के दायरे में ले जाया गया है और माना गया है उत्तराधिकार के किसी भी नियम का गठन करने वाले मूल कानून का

हिस्सा नहीं होना। सह-उत्तराधिकारियों की संपत्ति माना जाता है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे को सीधे उसके हाथ में नहीं दिया जा सकता है जब तक कि मुकदमे में पक्षकार होने वाले सह-उत्तराधिकारियों को ऋण के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है; कर्ज वसूली योग्य है। लेकिन यहां इसमें एक तथ्यात्मक पहलू शामिल है जिस पर रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है या नीचे की अदालत द्वारा मामले की जांच की गई है: हम इस स्तर पर इस मुद्दे को उठाने से इनकार करते हैं।

उपरोक्त कारणों से हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं। हम समान रूप से देर से की गई प्रति-आपत्ति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं अपील की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 2 की अनुमति मांगी गई थी। हम अनुरोध पर विचार करने से इनकार करते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

आर एस एस

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।